



तापमान 16 – 28
आर्द्रता 38%
सूर्योदय: 06:12 सूर्यास्त: 17:30

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर



समाज्ञा



आयकर की दरों में बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग निराश : राघव चड्ढा **पृष्ठ 7**

कोलकाता, फाल्गुन कृष्णपक्ष अष्टमी, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : मुस्कान वो मनोहर चाबी है जो कि हर दरवाजे का ताला खोल सकती है।



AI IMPACT SUMMIT
भारत 2026 INDIA

सर्वजन हिताय | सर्वजन सुखाय
WELFARE FOR ALL | HAPPINESS OF ALL

3 मार्गदर्शक सूत्र

मानव । पृथ्वी । प्रगति

16 से 20 फरवरी 2026 | नई दिल्ली, भारत

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें

एक ऐसे भविष्य को संवारना, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का परिवर्तनकारी प्रभाव मानवता की सेवा करे और पृथ्वी का संरक्षण करे।



बंगाल में बढ़ाई डेडलाइन, डीजीपी को भी नोटिस जारी

एसआईआर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

■ 'बंगाल में एसआईआर को बाधित करने के जानबूझकर प्रयास किये जा रहे', चुनाव आयोग ने कहा

■ 'ईआरओ ही लेगा अंतिम फैसला', माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश



स्पष्टीकरण जारी करेगी। पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्वाचन आयोग के इन आरोपों के सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि कुछ शर-रती तत्वों ने उसकी ओर से जारी नोटिस जला दिए हैं। पीठ ने एसआईआर कवायद के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को ग्रुप-बी के 8,505 अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराए जाने का संज्ञान लिया। उसने कहा कि इन अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया में प्रशिक्षित और नियोजित किया जा सकता है। पीठ ने प्रभावित व्यक्तियों की ओर

से पेश दस्तावेजों की जांच के लिए समय सीमा 14 फरवरी से एक सप्ताह आगे बढ़ा दी। उसने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है और समस सीमा बढ़ाने से मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को उचित फैसला लेने में मदद मिलेगी। पीठ पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है,

जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की आशंका जाहिर की गई है। पीठ ने कहा कि हम किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर कवायद को पटरी से उतारने, पुंगु बनाने और विफल करने के लिए जानबूझकर एवं सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पीठ ने विभिन्न निर्देश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्वाचन आयोग को ग्रुप-बी के जिन 8,505 अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई है, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया में प्रशिक्षित और नियोजित किया जा सकता है। उसने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये 8,505 अधिकारी मंगलवार को शाम पांच बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी या ईआरओ के समक्ष ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। पीठ ने

कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मौजूदा ईआरओ या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईईआरओ) को बदलने और इन अधिकारियों की उपयुक्तता के आधार पर इनकी सेवाएं लेने का अधिकार होगा। उसने कहा कि निर्वाचन आयोग इन 8,505 अधिकारियों के बायोडेटा और कार्य अनुभव की जांच करने के बाद इनमें से, पहले से ही कार्यरत सूक्ष्म-पर्यवेक्षकों की संख्या के बराबर अधिकारियों का चयन भी कर सकता है। पीठ ने कहा कि इन अधिकारियों को ईआरओ या ईईआरओ के साथ-साथ सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की सहायता करने के उद्देश्य से एक या दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में संशोधन के सिलसिले में अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन 8,505 अधिकारियों की निशुक्ति का तरीका और कामकाज निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया जाएगा।

टी20 विश्व कप में होगा भारत और पाकिस्तान का मैच

■ पाकिस्तान ने बहिष्कार का फैसला वापिस लिया

इस्लामाबाद/ढाका : भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा चूंकि पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश और श्रीलंका के समझाने के बाद इस मैच के बहिष्कार का फैसला वापिस ले

लिया है और इसके साथ ही टूर्नामेंट में जारी गतिरोध भी खत्म हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कोलंबो में 15 फरवरी को होना है। पाकिस्तान सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'बहुपक्षीय बातचीत के नतीजों और दोस्त देशों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वह 15 फरवरी 2026 को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का अपना निर्धारित मैच खेलने

मैदान पर उतरे।' बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इससे पहले जारी एक बयान में पाकिस्तान से क्रिकेट के हित में यह मैच खेलने का अनुरोध किया था। इसके बाद ही स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान यह मैच खेलेगा। पाकिस्तान सरकार के बयान में कहा गया, 'यह फैसला क्रिकेट की भावना की रक्षा और सभी प्रतिभागी देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता का समर्थन करने के मकसद से लिया गया है।'

‘नेशनल इंस्ट्रस्ट से तय होगा’, रूसी तेल खरीद पर विदेश मंत्रालय का क्लियर स्टैंड

नई दिल्ली : रूस के साथ तेल के व्यापार और अमेरिका के साथ 'ट्रेड डील' के बीच चल रही खींचतान पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए साफ कर दिया कि भारत के लिए एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा पैमाना केवल और केवल नेशनल इंस्ट्रस्ट है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। रूसी तेल खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दोहरा कहा, चाहे वह सरकार हो या व्यवसाय, हमारे विकल्पों में नेशनल इंस्ट्रस्ट ही हमारा गाइडिंग फैक्टर है। उनका यह बयान संकेत देता है कि



भारत किसी भी बाहरी दबाव के बजाय अपनी घरेलू जरूरतों और अर्थव्यवस्था के लाभ को प्राथमिकता देगा। उन्होंने रूस का नाम लिए बिना यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

डायवर्सिफिकेशन की रणनीति

विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत ऊर्जा आपूर्ति के अनेक स्रोतों को बनाए रखने की योजना पर काम कर रहा है। इसके पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

भारतीय उपभोक्ताओं को सही और सस्ती कीमत पर ऊर्जा मिले। देश की बढ़ती जरूरतों के लिए ऊर्जा की कोई कमी न हो। आपूर्ति के स्रोत विश्वसनीय और सुरक्षित हों, ताकि वैश्विक संकट के समय भी ऊर्जा प्रवाह बाधित न हो।

ट्रंप के दावे का क्या ?

विदेश सचिव ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत रूसी तेल का आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने पर सहमत हो गया है। कूटनीतिक गलियारों में इसे भारत की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस जैसे पुराने और सस्ते ऊर्जा साझेदार को खोना नहीं चाहता।

बंगाल में 28 फरवरी से पहले अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के प्रयास जारी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

■ लगभग 1.39 करोड़ मामलों की सुनवाई पूरी, लगभग 1.06 करोड़ मामलों में दस्तावेज अपलोड

■ अंतिम मतदाता सूची में नाम होने पर पांच दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को करें आवेदन

आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण 15 फरवरी तक पूरा करने के लिये कहा

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण और तैनाती 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (एसडीओ) के कार्यालय ने राज्य के गृह सचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि यह निर्देश 12 जनवरी की तिथि वाले पहले के पत्र के क्रम में जारी किया गया है। पत्र में, कहा गया कि मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि चुनाव से सीधे जुड़े पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण/तैनाती 15 फरवरी तक अवश्य पूरी कर लें। इसमें यह भी कहा गया है कि अनुपालन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करने के लिए तत्काल भेजी जानी चाहिए। पत्र में, समय पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य प्रशासन से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि पत्र की एक प्रति अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानूनी) और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी को भी जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई है।

निवारण के संबंध में बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वे पांच दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी आवेदन का निपटारा नहीं करते हैं, तो मतदाता अगले पांच दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

डिजिटल धोखाधड़ी के जरिये 54 हजार करोड़ रु का गबन ‘डकैती’ के समान, एसओपी बनाए केंद्र: न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के जरिये 54 हजार करोड़ रुपये के गबन को पूरी तरह से लूट और डकैती करार देते हुए सोमवार को केंद्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए आरबीआई, बैंकों और दूरसंचार विभाग जैसे हितधारकों के साथ चर्चा करके मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामलों से जुड़े खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने में बैंकों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारीया की पीठ ने कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उन खातों में असामान्य और बड़े पैमाने का लेनदेन होने पर ग्राहकों को सतर्क

करें, जिनका आम तौर पर छोटे लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है। पीठ ने कहा कि यदि सामान्यतः 10,000 या 20,000 रुपये की राशि निकालने वाला कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति अचानक बहुत बड़ी रकम निकालता है, तो बैंक को तुरंत अलर्ट जारी करना चाहिए। पीठ ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के जरिये गबन की गई धनराशि कई छोटे राज्यों के बजट से अधिक है। अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी लापरवाही के कारण हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आरबीआई और बैंकों की ओर से समय पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने सीबीआई को 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया और

गुजरात तथा दिल्ली की सरकार से कहा कि वे इन मामलों में जांच के लिए सीबीआई को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने के मामलों में एक व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने याचिका को चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई की शुरुआत में, अर्टोनी ज़ररल आर. वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि आरबीआई ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार किया है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगाए जाने जैसी कार्रवाई समेत कई प्रावधान हैं।

परीक्षा पे चर्चा के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए गुरुमंत्र

प्रौद्योगिकी का गुलाम न बनें, एआई का उपयोग मार्गदर्शन पाने के लिए करें



नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को छात्रों को सलाह दी कि वे प्रौद्योगिकी को उन्हे गुलाम नहीं बनाने दें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग मार्गदर्शन और अपने काम में बेहतरि लाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि सीखने के विकल्प के रूप में। प्रधानमंत्री के वार्षिक 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के नौवें संस्करण की दूसरी कड़ी में, मोदी ने कहा कि मोबाइल फोन उन कुछ बच्चों के मालिक बन गए हैं, जो उनके या टेलीविजन स्क्रीन के बिना खाना भी नहीं खा सकते। उन्होंने कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और गुजरात के विद्यार्थियों से हुई बातचीत में कहा, 'हर युग में नयी प्रौद्योगिकियों, चाहे कंप्यूटर हों या मोबाइल फोन, को लेकर चिंताएं रही हैं। लेकिन यह डर बेवजह है। आपको यह दृढ़ संकल्प लेना होगा

कि हम प्रौद्योगिकी के गुलाम नहीं बनेंगे।' प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से न डरें, बल्कि उनका उपयोग अपने कौशल को निखारने के लिए करें। उन्होंने कहा, 'हमें एआई या मोबाइल फोन को अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए, कुछ बच्चे स्मार्टफोन देखे बिना खाना नहीं खाते। हमें प्रौद्योगिकी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस प्रौद्योगिकी की ताकत को जोड़ना होगा, जो हमारे कामों में 'वैल्यू एडिशन' करें।' मोदी ने कहा कि काम का स्वरूप हमेशा बदलता रहेगा, जैसे परिवहन बैलगाड़ियों से हवाई जहाजों में परिवर्तित हुआ, लेकिन जीवन चलता रहा। उन्होंने कहा, 'किन्ती ही उत्तम से उत्तम प्रौद्योगिकी क्यों ना आए, हमारे लिए उपयोगी ही होने वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है।'



JAISWAL INDUSTRIAL PARK PHASE I & II

COMPLETE COMMERCIAL PLOTS AVAILABLE WITH FILLING AND BOUNDARY

JUST 3 MINS FROM DANKUNI HOUSING

CALL: 7003982830 email: udgeethdevelopers@gmail.com



DIVYANSH JAISWAL

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के सवाल

बीते शनिवार जारी किए गए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रारूप को लेकर उठ रहे सवालों ने फिर उस मूलभूत सवाल को पुख्ता किया है कि मुक्त व्यापार समझौते की कीमत कौन चुकाएगा? साथ ही यह भी कि इसका लाभ किसे मिलेगा? इस समझौते से जुड़ी आशंकाओं को लेकर कुछ किसान संगठन आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। निस्संदेह, उनकी आशंकाएं सिर्फ सोयाबीन तेल, सूखे अनाज और सेब पर आयात शुल्क में छूट को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और भारतीय कृषि के भविष्य को लेकर भी हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि किसान हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। निस्संदेह, कागजों पर तो ये आश्वासन राहत देने वाले लगते हैं, लेकिन व्यवहार में किसानों की आशंकाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ व न्यूजीलैंड के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के कारण सस्ते आयात में भारी वृद्धि हुई, फलतः कमजोर किसानों की दशा खराब हुई। निर्विवाद रूप से भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी सेब से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण होगा। हिमाचल के सेब उत्पादक संगठनों का कहना है कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क पचास से 25 प्रतिशत करना व न्यूनतम आयात मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम करने से यह स्वदेशी प्रीमियम सेवा के दाम पर बाजार में बिकने लगेगा। जिसके चलते भारतीय उपभोक्ता समान मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी सेब को तरजीह देंगे। साथ ही सेब का कोल्ड स्टोरेज में संग्रह करना अलाभकारी हो जाएगा।

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि कृषि और दुग्ध उद्योग संरक्षित रहेंगे। जबकि संयुक्त समझौते में कृषि और खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर शुल्क कम करने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है। कम आय, बढ़ती लागत और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे किसानों को इन गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता चाहिए। यही वजह है कि कई किसान संगठनों, विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद के समक्ष रखा जाए। निस्संदेह, यह मांग तार्किक है क्योंकि व्यापार समझौते भी घरेलू कानूनों की तरह ही आजीविका को गहराई तक प्रभावित करते हैं। कृषि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मजबूत घरेलू समर्थन, उचित मूल्य, सब्सिडी, बुनियादी ढांचे और जोखिम संरक्षण दिए बिना, बाजारों को खोलने के कदम छोटे और सीमांत किसानों पर भारी पड़ सकते हैं। इसी फिक्क के चलते हड़ताल एक चेतावनी है। यदि सरकार का मानना है कि यह समझौता वास्तव में किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है तो उसे पारदर्शिता, संसदीय बहस और सार्थक परामर्श के माध्यम से इसे साबित भी करना चाहिए। अन्यथा, सुधारों की कहानी एक बार फिर देश के अमरदाता की चिंताओं को दूर करने में विफल रहेगी। इसी तरह देश के सेब उत्पादकों को भी आश्चस्त करना होगा कि उनके सेब की खुशबू बरकरार रहेगी।

आज का पंचांग

कोलकाता : 10 फरवरी, मंगलवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2082, फाल्गुन कृष्णपक्ष अष्टमी, 07:27 तक, नक्षत्र : विशाखा, 07:48 तक, योग : ध्रुव, 25:38 तक, सूर्योदय: 06:12, सूर्यास्त: 17:30, चन्द्रोदय : 00:19, चन्द्रास्त: 11:13, शक सम्वत: 1947 विश्वावसु, सूर्य राशि : मकर, चन्द्र राशि : वृश्चिक, राहू काल : 14:38 से 16:02

राशिफल

मे़ष : मे़ष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन शुभ रहने वाला है। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी व्यक्ति या संस्था से कई कर्ज लेने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें।
वृष : मंगलवार का दिन वृ़षभ राशि के जातकों के लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। काम-काज को लेकर ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना नज़र आ रही है।
मिथुन : मिथुन राशि के लोगों के लिए मिलानुला रहने वाला है। अगर आप पहले से किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं तो आज कष्ट की वृद्धि हो सकती है। सामाजिक क्रियाकलापों में अड़चन आएगी।
कर्क : कर्क राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी रहने वाला है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आज आपके द्वारा किए गए परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा।
सिंह : सिंह राशि का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। दिन का मध् बाग आपके लिए उत्तम रहेगा।
कन्या : कन्या राशि के जातकों के अंदर आज निर्भिकता का भाव रहेगा। कठिन कार्यों को आप आसानी से सम्पन्न करने में सफल रहेंगे। आपको अपने माता-पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा।
तुला : तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों के साथ ही आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। आज आप दूसरों की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।
वृश्चिक : वृश्चिक राशि के जातकों का मन अशांत और परेशान रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। प्रतिभा के चल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।
धनु : आज के दिन आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके अन्दर दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी। आप धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेकर पूर्ण सहयोग करेंगे।
मकर : मकर राशि के लोगों के लिए आज दिन कल्याणकारी रहने वाला है। हनुमान जी की कृपा से आज आपको बहुमुल्य वस्तुओं की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
कुम्भ : कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बुद्धि-विवेक का अधिक प्रयोग करने वाला रहेगा। आपका दिन नई-नई खोज करने में व्यतीत होगा। नौकर चाकरों का भी सुख मिलेगा।
मीन : मीन राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कुछ अटके हुए कार्यों की पूर्ति कराने वाला रहेगा। बहुत समय से फंसा हुआ पुत्र या पुत्री से संबंधित किसी विवाद का हल निकल जाएगा।

हड़ताल श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है



एस. पी. तिवारी

अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन में आसानी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य, बिना जटिल उद्योग वर्गीकरण की बाधाओं के, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देना है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनिवार्य पहचान पत्र की शुरुआत करते हुए, ये संहिताएं उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीधी पहुंच की सुविधा के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, श्रमिकों की भलाई में मदद करेंगी, जिससे ये स्वस्थ और

अधिक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा, समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था, पीड़ित श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव और अनिश्चितता को कम करने में सहायता करेगी। समग्र रूप से, ये उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित एक प्रगतिशील रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक प्रावधानों के बावजूद, राजनीतिक रूप से प्रेरित केंद्रीय श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) का एक हिस्सा अक्सर हड़ताल के प्रतिकूल प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना, हड़ताल पर उतर आता है। ऐसी हड़तालों से विशेष रूप से केंद्रित अर्थव्यवस्था के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के पारिश्रमिक को भारी नुकसान होता है, जो अपनी जीविका के लिए दैनिक आय पर निर्भर होते हैं। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, बार-बार होने वाली हड़तालें रचनात्मक और कठोर

सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत और संतुलित परिणाम हासिल करने की संभावना कम हो जाती है।

समय के साथ, बार-बार हड़ताल बुलाने का प्रयास न केवल अप्रभावी साबित हुआ है बल्कि इसके परिणाम प्रतिकूल भी रहे हैं। बार-बार होने वाली हड़तालों से श्रमिकों में व्यापक शकान दिखाई पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे आह्वान को या तो नजरअंदाज करते हैं या उनमें शामिल नहीं होते हैं। कुछ मामलों में, श्रमिकों के एक छोटे हिस्से को उनकी इच्छा के विपरीत हड़तालों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इन आंदोलनों की नैतिक वैधता व सामूहिक ताकत और कमजोर हो जाती है। अंततः, यह प्रवृत्ति श्रमिक कल्याण उपायों के समग्र प्रभाव को कम करती है और श्रमिकों के बीच एकजुटता को कमज़ोर करती है।

साझेदारी या संप्रभुता का सौदा?



डॉ घनश्याम नादल

संसे – जै से भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की डिटेल्स सामने आ रही हैं व्यापार और संप्रभुता के सवाल भी नहीं जोर शोर से हवा में उछलते दिखाई देने लगे हैं। जहां

सरकारी पक्ष इसे ‘मदर ऑफ ऑल डीलस्’ कहे जाने वाली फ्री ट्रेड डील के बाद ‘फादर ऑफ ऑल डीलस्’ कहकर अपनी पीठ थपथपा रहा है और भारत की बढ़ती हुई हैसियत का हवाला दे रहा है वहीं विपक्ष व्यापार के नाम पर अपनी संप्रभुता से समझौता तथा अमेरिका के आगे घुटने टेकने का उपक्रम बता रहा है। बेशक यह रणनीतिक साझेदारी का स्वाभाविक विस्तार कहा जा सकता है । सरकार भी इसे वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश के साथ आती है इस समझौते में भी बौद्धिक संपदा कानूनों में कोठरता,कृषि, डेयरी और फार्मा बाज़ार खोलने की मांग, डिजिटल टैक्स और डेटा नीति में हस्तक्षेप नज़र आ रहा है । आशंका यह भी है कि यह धीरे-धीरे भारत की नीतिगत संप्रभुता को सीमित कर सकता है। ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सीमाओं से नहीं आती, वह नीतियों से आती है,और जब नीतियाँ बाहरी दबाव से तय हों, तो संप्रभुता प्रतीक मात्र रह जाती है।

विकास या संरचनात्मक निर्भरता ?

यदि इस समझौते के सकारात्मक आर्थिक

प्रभावों को देखें तो अमेरिकी निवेश से पूंजी

प्रवाह बढ़ेगा, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल

और इंजीनियरिंग निर्यात को अमेरिकी बाज़ार

मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर

को गति मिलेगी लेकिन इस रास्ते पर चलने

रणनीतिक गठजोड़ या नीतिगत दबाव: सरकार और उसके समर्थकों के अनुसार भारत-अमेरिका ट्रेड डील से भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति मजबूत होने जा रही है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक संतुलन, चीन के प्रभाव का प्रतिकार और लोकतांत्रिक शक्तियों के गठबंधन के लिए यह समझौता एक राजनीतिक आधार बनेगा तथा भारत को वैश्विक मंच पर ‘विश्वसनीय साझेदार’ की पहचान मिलेगी। लेकिनकट्ट यथार्थ यह भी है कि अमेरिकी ट्रेड डील कभी बराबरी की शर्तों पर नहीं होती। वह हमेशा नीति-संशोधन के दबाव के साथ आती है इस समझौते में भी बौद्धिक संपदा कानूनों में कोठरता,कृषि, डेयरी और फार्मा बाज़ार खोलने की मांग, डिजिटल टैक्स और डेटा नीति में हस्तक्षेप नज़र आ रहा है । आशंका यह भी है कि यह धीरे-धीरे भारत की नीतिगत संप्रभुता को सीमित कर सकता है। ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सीमाओं से नहीं आती, वह नीतियों से आती है,और जब नीतियाँ बाहरी दबाव से तय हों, तो संप्रभुता प्रतीक मात्र रह जाती है।

विकास या संरचनात्मक निर्भरता ?

यदि इस समझौते के सकारात्मक आर्थिक प्रभावों को देखें तो अमेरिकी निवेश से पूंजी प्रवाह बढ़ेगा, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग निर्यात को अमेरिकी बाज़ार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर को गति मिलेगी लेकिन इस रास्ते पर चलने

भारत अमेरिका ट्रेड डील :

के जोखिम भी कम नहीं हैं क्योंकि भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव बढ़ेगा, अमेरिकी सब्सिडी आधारित कृषि उत्पादों से भारतीय किसान संकट में आ सकते हैं, डिजिटल सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार की आशंका भी डराने वाली है। जानकारों का मानना है कि यह मॉडल ‘आत्मनिर्भर विकास’ नहीं, बल्कि निर्भरता आधारित विकास को जन्म देगा जहाँ ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन नियंत्रण बाह्य काहोता है।

अवसरों का विस्तार या असमानता का विस्फोट ?

यदि सामाजिक दृष्टि से देखे तो इस डील के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं सकारात्मक प्रभाव में शहरी युवाओं के लिए रोजगार अवसर, वैश्विक स्किल एक्सचेंजर, शिक्षा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी सहयोग शामिल हैं तो नकारात्मक पक्ष के रूप में ग्रामीण-शहरी खाई का विस्तार, पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों का क्षरण, गिग इकॉनोमी का विस्तार, न सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी आता दिखाई दे रहा है ।

आशंका यह भी है कि यह समझौता एक ऐसा समाज गढ़ सकता है जहाँ एक छोटा

राज्यों की खबरें

सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा : योगी आदित्यनाथ



वाले दलित हिंदू हैं। धर्माचार्यों व कुछ हिंदू संगठनों का छोड़ दिया जाए तो कोई मानवाधिकार या दुनिया का संगठन उनकी वकालत करने वाला नहीं है।” योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”दुनिया में तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गईं, लेकिन सनातन संस्कृति तमाम तूफानों को झेलते हुए आज भी गरिमा-गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ

वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दे रही है। इसे तोड़ने के लिए अनेक प्रयास हुए।” उन्होंने कहा, ” सनातन धर्मावलंबियों ने विपत्ति के समय हर किसी को शरण देकर उसे पुष्पित-पहुँचित होने का अवसर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी धर्म का निर्वहन नहीं किया, बल्कि यहां आकर हाथ की अंगुली पकड़कर गला दबाने का प्रयास किया और देश को लूटने में कसर नहीं छोड़ी।”

वर्ग पहेली नं. 3347

1	2	3	4	5	
		6		7	
8			9	10	11
		13	14	15	16
			17		18
20	21			22	
			23	24	25
26		27		28	
			29		30

बायें से दायें:-
1) श्रामियाना की दीवार,
3) मुकरना,
5) एक बदा दो,
6) चुनौती,
7) बुद्ध,
8) दंगा-फ़साद,
9) बार-बार दोहराना,
11) रहस्य,
13) घूल,
15) खाने-पीने की सामग्री,
17) ज्ञापक़ा; बानगी,
18) मुसलमान,
20) अक्कीर,
23) झगड़ा,
25) रम्पणीय,
26) आगामी,
28) तिरछी नज़र,
29) विपत्ति; दुर्भाग्य,
30) श्रम.

ऊपर से नीचे:-
1) लाभभग,
2) एक शक्व,
3) अस्वीकृति; इनकार,
4) बक-बक करना,
5) एक भारतीय शहर,
10) दिव्यंस; बर्बादी,
12) भाषा; जीभ,
14) लोक-मत,
16) नेत्र,
19) फोरस्ट रेंजर,
21) हेक्झीवाज़,
22) पन्ना,
24) झगड़ालू स्त्री,
26) कम,
27) वैध; प्रचलित.
(उत्तर: अगले अंक में)

पिछली पहेली का उत्तर

पू. क्र. द. आ. व. भा. ग. त.
न. री. म. सा. ही. धा. र.
त. ल. च. ओ. र. स. फ़.
या. त. री. क़. वे. ज़. य. दा.
को. री. त. प. च. च. र.
आ. न. या. ट. ना. ट. न.
शी. घ. र. सा. र. जा.
वा. ला. ग. नी. मा. त. हि.
द. र. कि. ना. र. त. क. दी. र.

हड़तालों के व्यापक परिणाम केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहते। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, दैनिक यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है, और सड़क किनारे के विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों और छोटे सेवा प्रदाताओं की आजीविका बाधित हो जाती है। इन श्रमिकों के लिए, केवल एक दिन की आय का नुकसान भी आजीविका संकट पैदा कर सकता है, उन्हें अपनी सीमित बचत को खत्म करने तथा गंभीर आर्थिक असुरक्षा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है।

भारत जैसी उपरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) को संवाद, आपसी-बातचीत और नियोक्ताओं तथा सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थायी सौदेबाजी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित एक मॉडल उत्पादन, रोजगार, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बाधित किए बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान

कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रभावी और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

भारतीय श्रमिक को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारु रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घावधि में सुरक्षित किया जा सकता है।

(लेखक ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

आरेडिका की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता, जीएम की पुस्तक टेल्स फ़ॉम रेल्स का विमोचन

रायबरेली : आधुनिक रेल डिब्बा

कारखाना, रायबरेली (आरेडिका) में

आयोजित प्रेस वार्ता में महाप्रबंधक

प्रशांत कुमार मिश्रा ने वित्तीय वर्ष

2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक

की उपलब्धियों की जानकारी साझा

की। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2014

से अब तक कारखाने में कुल

15,369 रेल डिब्बों का निर्माण किया

जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में

1,679 डिब्बे तैयार कर रेलवे को

समर्पित किए गए, जिनमें से 1,600 डिब्बे सामान्य

शयनयान श्रेणी के हैं, जो आम यात्रियों की सुविधा को

ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। वंदे भारत चैयर कार

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा

रहे हैं और 16 डिब्बों वाली पहली वंदे भारत चैयर कार

रेक का निर्माण फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। फोर्ड

व्हील उत्पादन में भी आरेडिका ने उल्लेखनीय प्रगति की

है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 50,000 पहियों के लक्ष्य

के मुकाबले जनवरी 2026 तक 54,075 पहियों की

फॉर्जिंग, 50,751 की मशीनिंग और 49,166 पहियों की



स्टैम्पिंग पूरी की जा चुकी है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ‘एक पेड़ मात्र के नाम’ अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया है। वर्षा जल संचयन संरचनाओं, तालाबों और रिचार्ज बोरेवेल के माध्यम से 748 मिलियन लीटर जल संचयन क्षमता विकसित की गई है। इस अवसर पर महाप्रबंधक की पुस्तक टेल्स फ़ॉम रेल्स का विमोचन भी हुआ। पुस्तक में भारतीय रेल से जुड़ी 32 सत्य घटनाओं पर आधारित रोचक कथाएं संकलित हैं। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, रेल इतिहास प्रेमी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

....

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3304 का उत्तर												
6	4	1	8	7	3	2	5	9				
8	3	5	2	4	9	1	6	7				
7	9	2	6	5	1	3	8	4				
9	5	6	1	8	4	7	2	3				
1	2	4	7	3	5	8	9	6				
3	7	8	9	6	2	5	4	1				
2	1	7	4	9	8	6	3	5				
4	6	3	5	2	7	9	1	8				
5	8	9	3	1	6	4	7	2				

सांसदों का निलंबन वापस लेने के लिए बिरला को पत्र लिखेगी टीएमसी : अभिषेक बनर्जी

नयी दिल्ली/कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन वापस लेने पर विचार करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अभिषेक इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज करते आए कि क्या उनकी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों द्वारा लाये जा सकने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। उनका सिर्फ यह कहना था कि इस मुद्दे पर उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले



और सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष को भी बोलने का समय मिलना चाहिए। लोकसभा सस्स्थ ने कहा कि आठ सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार करने और संसद के भीतर लोकातांत्रिक संतुलन बहाल करने के लिए औपचारिक रूप से अध्यक्ष के समक्ष अपील की जाएगी। तृणमूल ने 'एक्स' पर बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के दौरान कथित उत्पीड़न की आलोचना करते हुए कविता लिखी

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक कविता साझा की, जिसमें उन्होंने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लोगों के कथित उत्पीड़न की आलोचना की है। 'आमी अस्वीकार कोरी' शीर्षक वाली कविता में एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख करने वाले प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ असंतोष जाहिर किया गया है, जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इसके चलते आम नागरिकों को असुविधा और परेशानी हुई है। अभिषेक ने 'एक्स' पर बांग्ला में लिखी इस कविता को साझा करते हुए कहा कि मैंने जिंदगियों को बर्बाद करने वाली एक कपटपूर्ण प्रक्रिया के कारण मेरे अंदर मची गहरी उथल-पुथल और इसके कारण लोगों को हुई तकलीफ, दर्द और उनके जायज आक्रोश को एक विनम्र कविता में ढाला है। कविता में अभिषेक ने खुद को लोगों की कथित तकलीफों का 'गवाह' बताया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से कथित तौर पर जुड़े उत्पीड़न और मौतों के मामलों का हवाला दिया है। कविता में संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए धारदार भाषा और राजनीतिक चित्रण का इस्तेमाल किया गया है, जो एसआईआर को लेकर पार्टी की आलोचना को प्रतिध्वनित करता है। तृणमूल नेताओं ने कहा कि अभिषेक की कविता का मकसद आम मतदाताओं की चिंता को उजागर करना और एसआईआर से जुड़ी अनियमितताओं पर प्रकाश डालना है।

के बयान साझा करते हुए कहा कि लोकसभा में हमारे नेता ने स्पष्ट रूप

से कहा कि सदन का सुव्यवस्थित संचालन आवश्यक है, लेकिन

विपक्षी सांसदों को बोलने का समय और अवसर मिलना चाहिए।

कर चोरी मामला : आयकर विभाग ने कोलकाता में 20 स्थानों पर की छापामारी

प्रभावशाली व्यवसायी और रियल एस्टेट प्रमोटर निशाने पर

कोलकाता, समाज्ञा : आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को कर चोरी के मामलों में कोलकाता में 20 स्थानों पर छापामारी की। इनमें दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित राजा संतोष रोड पर एक प्रभावशाली व्यवसायी का आवास भी शामिल था। दक्षिण कोलकाता के चेतला स्थित उक्त व्यवसायी के कार्यालय में भी एक साथ छापामारी और तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों ने बताया कि कारोबारी और उसके स्वामित्व वाली संस्था के खिलाफ पहले से दायर आयकर चोरी और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया।

आयकर अधिकारियों की एक अन्य टीम ने न्यूटाउन के एक्सन एरिया-तीन में एक पाश हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अन्य व्यवसायी के आवासीय फ्लैट पर एक साथ छापामारी की। इसी तरह, तीन और कार्यालयों में छापामारी और तलाशी अभियान चलाया गया, जिनमें से एक न्यूटाउन के इकोस्पेस में, दूसरा मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में और तीसरा दक्षिण कोलकाता में गुरुद्वार दत्ता रोड के पास स्थित है। ये सभी कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर आयकर चोरी, बेहिस्साब संपत्ति और आय के अनुपात से अधिक संपत्ति के मामलों से संबंधित हैं। उत्तर 24

परगना जिले के बारासात स्थित दक्षिणपाड़ा रोड पर शीतलातला मंदिर के समीप मुखर्जी परिवार के आवास पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि परिवार के एक सदस्य सत्यनारायण मुखर्जी के जमीन खरीद-बिक्री और प्रमोटिंग व्यवसाय से जुड़े होने के कारण यह आयकर कार्रवाई की गई हो सकती है। हालांकि, किस ठोस शिकायत या सूचना के आधार पर यह तलाशी ली जा रही है, इस संबंध में आयकर विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने कहा है कि लड़कियों के लिए पूर्ण समानता हासिल करने के वास्ते समाज को अभी लंबा रास्ता तय करना है। अदालत ने डेढ़ साल की बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाली महिला के ससुराल वालों को उसके उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। पोर्ट ब्लेयर सत्र न्यायालय ने महिला के ससुराल वालों को बरी कर दिया था। उन पर आरोप था कि वे महिला को प्रताड़ित करते थे और उसके माता-पिता से देहेज की मांग करते थे, खासकर बच्ची के जन्म के बाद।



महिला ने 2021 में अपनी बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के सास, ससुर, देवर और देवरानी को चार हफ्ते के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष की अपील पर छह फरवरी को फैसला सुनाते हुए

कोयला तस्करी मामला : ईडी ने बुदबुद पुलिस थाना प्रभारी को पूछताछ के लिए किया तलब

लाला के करीबी चिन्मय मंडल भी तलब



कोलकाता, समाज्ञा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बुदबुद पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने बुदबुद पुलिस थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल के आवास पर तलाशी लेने के कुछ दिन बाद उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया है। तलाशी के दौरान मंडल के आवास से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि मनोरंजन मंडल से पूछताछ कोयला तस्करी के खिलाफ

ममता सरकार ने 12 शरणार्थी कॉलोनियों को दी मान्यता

निवासियों को मिलेगा भूमि अधिकार, निवास प्रमाण पत्र



कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए विभिन्न जिलों की 12 शरणार्थी कॉलोनियों को भूमि आधिकारिक मान्यता देने का निर्णय लिया है। नवरा (राज्य सचिवालय) सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में इन कॉलोनियों के निवासियों को भूमि अधिकार और निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी और निजी भूमि पर स्थित इन 12 कॉलोनियों की सूची में उत्तर दिनाजपुर की बीरनगर कॉलोनी और उत्तर 24 परगना की

विधानसभा में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई

कॉलोनियों को दी मान्यता



कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अदालत की अवमानना के दायरे में नहीं आती। यह मामला विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी द्वारा दायर किया गया है, जिसमें विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मियों के प्रवेश की वैधता को चुनौती दी गई है। राज्य की ओर से दलील देते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों संवैधानिक पदों पर आसीन हैं,

इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रावधानों को अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि अदालत फिलहाल मामले की गहराई में जाने की इच्छुक नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगली सुनवाई तक विधानसभा के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। साथ ही, अध्यक्ष द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी अधिसूचना सभी विधायकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

आरजी कर मामला : मशाल रैली निकालकर जन्मदिन पर महिला चिकित्सक को किया गया याद

क रेल क ता, समाज्ञा : कोलकाता में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने एक मशाल रैली निकाली और आरजी कर अस्पताल की डॉ. अभया को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। बता दें कि नौ फरवरी को डॉ. अभया का जन्मदिन होता है और अगस्त 2024 में उनकी अस्पताल में दुर्घर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी। नागरिक समाज के सदस्यों, विद्यार्थियों और पेशेवरों के एक मंच 'अभया के लिए न्याय' फोरम द्वारा निकाली गयी इस रैली में आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति को छोड़कर, इस बड़ी साजिश में शामिल अन्य लोगों की अब तक



पहचान नहीं हो पाई है। फोरम ने राज्य और केंद्र दोनों की जांच एजेंसियों पर शहर के बीच-बीच एक सरकारी अस्पताल में हुए इस घटना अपराध का पर्दाफाश करने में तत्परता न दिखाने का भी आरोप लगाया। सोमवार को अभया के 33वें जन्मदिन पर उसके माता-पिता ने उसकी तस्वीर के सामने 33 गुलाब रखे। पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। नौ

अगस्त, 2024 को हमारी इकलौती बेटी पर हुए क्रूर अत्याचार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हा सकता। हम मांग करते हैं कि इस संस्थागत अपराध में शामिल सभी लोगों की पहचान की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डॉ. अभया की मां ने पत्रकारों से कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता, हम तब तक तक लड़ते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सोदपुर ट्रैफिक मोड़ पर दो किलोमीटर दूरी मोमबलियां जलाई। प्रदर्शनकारियों ने एस्प्लेनेड डोरिना क्रॉसिंग और शहर के श्यामबाजार इलाके में भी इकट्ठा होकर न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

विधानसभा चुनाव : भाजपा का 'रिवर्स गेम प्लान', सर्वे में पहली बार सामने आया 'नो-कैंडिडेट' फॉर्मूला

पिछले चुनावों की गलतियों से सीख रही भाजपा, पैरवी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। पार्टी इस बार केवल जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश ही नहीं कर रही, बल्कि उन चेहरों की भी शिनाख्त कर रही है जिन्हें किसी भी हाल में टिकट नहीं दिया जाना है। दिल्ली के सीधे निर्देश पर हो रहे एक गोपनीय सर्वे में हर सीट से तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम के साथ-साथ तीन ऐसे नाम भी भेजे जा रहे हैं, जिनके प्रति जनता और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। 2021 के विधानसभा चुनाव और

2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों से सीख लेते हुए भाजपा नेतृत्व इस बार 'पर फ्रूक तमाशा' देखने के मूड में नहीं है। पिछले चुनावों में 'योगदान मेला' के जरिए दूसरे दलों से आए भारी-भरकम नेताओं और टॉलीबुड के सितारों को टिकट देने का दांव उल्टा पड़ गया था। बाहरी नेताओं के 'उड़कर आने और जुड़ जाने' की प्रवृत्ति ने जमीन पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया था। इसी 'सिद्धे मेघ' (आश्ंका के बादल) को टालने के लिए पार्टी ने अब पेशेवर एजेंसियों के जरिए समानांतर सर्वे कराया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय



नेतृत्व के इशारे पर पेशेवर सर्वेक्षकों ने हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,000 से 1,200 लोगों से फीडबैक लिया है। इसमें दो सूचियां तैयार की गई हैं। पहली सूची में उन तीन लोगों के नाम हैं जिन्हें जनता पसंद कर रही है। वहीं, दूसरी 'नैगेटिव लिस्ट' में

उन तीन लोगों के नाम दर्ज हैं जो टिकट पाने के लिए बड़े नेताओं की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी छवि खराब है। सूत्रों का कहना है कि इस 'ना-पसंद' सूची में दक्षिण बंगाल के कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से अधिकांश वे नेता हैं जो पहले तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भाजपा में आए थे। उत्तर बंगाल की तुलना में दक्षिण बंगाल में ऐसे नेताओं की संख्या अधिक है। विशेष रूप से राजाहाट-न्यूटाउन, बिधाननगर और चंडीपुर जैसी सीटों पर राज्य स्तर के कुछ 'परिचित चेहरों' को जनता ने सिर से नकार दिया है।

भाजपा के इस कदम का मुख्य उद्देश्य 'टिकट के जुगाड़' को खत्म करना है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ नेता दिल्ली या कोलकाता के बड़े पदाधिकारियों से अपनी निरुत्तरता का फायदा उठाकर टिकट पा लेते हैं। अब, यदि किसी नेता का नाम सर्वे की 'नैगेटिव लिस्ट' में आ गया, तो कोई भी सिफारिश उसे चुनाव मैदान में नहीं उतार पाएगी। मंडल स्तर के पदाधिकारियों से अब इन 'ना-पसंद' नामों पर फीडबैक लेकर उनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है, ताकि टिकट वितरण के समय चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

MATRIMONIAL

EDUCATION

OBITUARY

PROPERTY

NAME CHANGE

REMEMBRANCE

RECRUITMENT

PUBLIC NOTICE

DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | samagya.in

81, Chintamani Dey Road, Howrah 711 101, Mobile: 70444 44522

मा सके। यह
-दुमका खंड
क्रमण-प्रवण
श्वेत करने की
मानी जा रही
हना है कि इन
सुरक्षा बढ़ेगी
सुचारु और
ग्र परिचालन
।

कोलकाता, समुदाय : जेटस्पॉन्स और शुवाब की सयुक्त एंजिनरी के अनुसार, कोलकाता में ईस्पॉन्स को लेकर खिलाड़ियों का भरोसा काफी लगातार मजबूत हो रहा है। सर्वे में शामिल 77% नियमित ईस्पॉन्स खिलाड़ियों ने इसे आर्थिक रूप से लाभकारी करियर बताया, जबकि नौजवान 44% ने इसे बहुत फायदेमंद माना। साथ ही, 73% खिलाड़ियों ने कहा कि वे ईस्पॉन्स को पेशेवर रूप से अपनाने पर विचार कर चुके हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि खिलाड़ी केवल प्रतिस्पर्धी गेमिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते। 60% स्टीमिंग या कंटेंट क्रिएशन, 43% टीम मैनेजमेंट में रुचि रखते हैं। ईस्पॉन्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 90% प्रतिभागियों ने सरकारी मान्यता और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरी बताया, जबकि 91% ने करियर काउंसलिंग और मेंटरशिप की आवश्यकता बताई। लगभग 68% खिलाड़ी पेशेवर ईस्पॉन्स खिलाड़ियों को एंथेलीट मानने में सहज हैं। 90% प्रतिभागियों नियमित रूप से टूर्नामेंटों में देखते हैं, जो शहर में ईस्पॉन्स की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

न्यूज़ इन ब्रीफ

झारखंड के गुमला में वाहन की टक्कर से दो नाबालिगों की मौत

रांची: झारखंड के गुमला जिले में अलग अलग घटनाओं में वाहन की टक्कर से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार को कामडारा-बेरो मुख्य सड़क पर हुई। पुलिस ने बताया कि फिल्मोन किन्डो (18) अपने नाबालिग मित्र के साथ परीक्षा केंद्र जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पटना दीवानी प्रदालत में बम की धमकी के कारण कामकाज ठप, पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

पटना: पटना दीवानी अदालत परिसर को सोमवार को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस ने गहन तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक महीने में बम की धमकी की यह दूसरी घटना है। एहतियातन अदालत का कामकाज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण अन्य मामलों के साथ-साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई नहीं हो सकी। यादव के वकील शिवनंदन भारती ने संवाददाताओं से कहा, "हमें बताया गया है कि जिला न्यायाधीश के इमेल पर बम की धमकी मिली है। इसके कारण सांसद की जमानत अर्जी पर अब कल से पहले सुनवाई नहीं हो सकेगी। मेरे मुवकिल को एक और दिन जेल में बिताना होगा।"

बिहार के मधेपुरा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 70 से अधिक बच्चे हुए बीमार

मधेपुरा: बिहार में मधेपुरा जिले के एक सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 70 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार को मधेपुरा सदर प्रखंड में करू टोला के मध्य विद्यालय में हुई। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संजय कुमार ने कहा, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि भोजन करने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी आने लगी तथा उन्होंने पेट दर्द और चक्कर आने की भी शिकायत की। स्थानीय लोगों का दावा है कि खाने में छिपकली गिर गई थी। एक अधिकारी के मुताबिक बच्चों को तुरंत मधेपुरा सदर अस्प-ताल ले जाया गया।

समाचार

व्रत – त्यौहार

12.02.2026 : स्वमी दयानंद सरस्वती जयंती

13.02.2026 : विजया एकादशी व्रत,कुंभ संक्रांति

14.02.2026 : शनि प्रदोष व्रत

15.02.2026 : महाशिवरात्रि व्रत

जब भगवान दुविधा में

मिथिलेश कुमार सिंह

एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए! कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो भगवान के पास भागा-भाग आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता !

अंततः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले- देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूं ! कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता हैं जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूं, फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता हैं जिससे न तो मैं कहीं शांति पूर्वक रह सकता हूं, न ही तपस्या कर सकता हूं ? आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुंच सके !

प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। सूर्य देव बोले-आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा-यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच

सत्र की कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद के माध्यम से अपनी बात रखें सभी सदस्य: योगी की अपील



लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि किसी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद के माध्यम से अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और यह उनकी सरकार का 10वां बजट है। उन्होंने एक बार फिर सभी सदस्यों से अपील की कि सदन की गरिमा बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने

कहा, 'परंपराओं के अनुसार बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र के दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं-पहला राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट।' सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समवेत सदन को संबोधित करते हुए अभिभाषण दिया। हालांकि, इस दौरान विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने विरोध-प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने कहा, 'विधानमंडल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यदि किसी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद के माध्यम से अपनी

राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी, राज्य में औषधि उत्पादन की अपार संभावनाएं:भजनलाल शर्मा



जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी हैं, यहां औषधि उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की पहाड़ियां, वन और समृद्ध जैव विविधता आयुर्वेद से इसके लंबे जुड़ाव को दर्शाती हैं तथा यहां की भूमि सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रही है। उन्होंने कहा, हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझा है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट जी जैसे महान वैद्यों ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दिया। राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसे

व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 1976 में एक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था जो आज देश के प्रमुख आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले पांच दशकों में नेतृत्व स्थापित किया है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में बढ़ते निवेश और संस्थान के विस्तार ने पूरे देश में आयुर्वेद को नई ऊर्जा दी है।

विधान भवन के अंदर-बाहर सपा का विरोध प्रदर्शन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन के मुख्य द्वार पर और सदन के भीतर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सभागार में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को समवेत संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किए जाते ही सपा के वरिष्ठ सदस्य डॉ. संग्राम यादव ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया। सपा सदस्यों की नारेबाजी के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया। विपक्षी दल के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और 'माता अहिल्याबाई का अपमान-नहीं सहेंगा हिंदुस्तान' जैसे नारे लगाने लगे। सपा सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण को 'झूठ का पुलिंदा' बताते हुए नारेबाजी की जो अभिभाषण समाप्त होने तक जारी रही। सदन में सपा सदस्य हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे थे। सपा सदस्य इंजीनियर सचिन यादव माता अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीर और पीठ पर मणिकर्णिका घाट की तस्वीर छपा कुर्ता पहनकर आए, जबकि सपा सदस्य अतुल प्रधान अहिल्याबाई की बड़ी तस्वीर लेकर सदन में पहुंचे।

बात रखें क्योंकि सरकार संवाद से समस्या के समाधान में विश्वास करती है।" उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2026-27 का सामान्य बजट 11 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी। बजट सत्र नौ फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत

महिलाओं के लिए राजद ने कुछ नहीं किया: नीतीश; राबड़ी ने किया पलटवार

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानपरिषद में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उसने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। यह टिप्पणी विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य में कथित रूप से बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर प्रदर्शन के बीच की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य दुष्कर्म की हाल की घटनाओं पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं आम बात बन गई हैं। हंगामे के बीच सदन में मौजूद मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए।

पति पर एक हजार रुपये के बदले अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

बदायूं (उप्र): बदायूं के फैजगंज बेहटा क्षेत्र में कथित रूप से एक हजार रुपये के बदले अपनी पत्नी को अपने दोस्तों की हसक का शिकार बनवाने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से सोमवार को बताया कि फैजगंज बेहटा क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया है कि रविवार शाम गैस एजेंसी पर जाते समय उसके पति ने बाल किशन और पप्पू नामक युवकों से एक हजार रुपये लिये तथा उसे उनके साथ भेज दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि रास्ते में दोनों ने एक बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद पुलिस चौकी पर पहुंची महिला ने शिकायत की, जिसके आधार पर बाल किशन, पप्पू और महिला के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

बिहार में 1995-2015 के बीच धार्मिक यात्रा पर आए 173 विदेशी, 167 पाकिस्तानी : सम्राट चौधरी

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि 1995 से 2015 के बीच धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से राज्य में कुल 173 विदेशी नागरिक आए, जिनमें से 167 पाकिस्तान से थे। सम्राट ने कहा कि शेष आगंतुक ब्रिटेन, रूस और उज्बेकिस्तान से थे, और सभी अपने-अपने देश लौट गए। मंत्री ने यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिथिलेश तिवारी की ओर से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में दी। गृह मंत्री ने सदन को आश्चस्त किया कि धार्मिक यात्रा पर आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि न हो। उन्होंने कहा कि इमीग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करती हैं और संदिग्ध मामलों में कार्रवाई की जाती है। तिवारी ने धार्मिक यात्राओं की आड़ में विदेशी नागरिकों की पहचान, सत्यापन और दीर्घकालिक मौजूदगी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन या धार्मिक यात्रा के बहाने आने वाले कुछ लोग बाद में स्थानीय समाज में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि उनकी आधिकारिक पहचान घुंघली पड़ जाती है।



राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब ये लोग सत्ता में थे, तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 2005 में हमारे सत्ता में आने के बाद बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है और राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उपसभापति रामबचन राय से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया।

हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री और विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई, लेकिन माइक्रोफोन बंद होने के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति रामबचन राय ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

धर्म-अध्यात्म

कलयुग के जीवित देवता हनुमान

देखकर उन्होंने इसे दूसरा राहु समझ लिया। तभी इंद्र ने पवन पुत्र पर वज्र से प्रहार किया जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी व उसमें टेटापान आ गया। इसी कारण उनका नाम भी हनुमान पड़ा। हनुमानजी की पूजा में सिंदूर और तेल का खासा महत्व है। सिंदूर की कथा सीता से जुड़ती है। एक बार माता सीता को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते देखा तो पूछ बैठे, 'माता ये क्या लगा रही हैं?' सीता ने बताया, 'सिंदूर लगा रही हूं, इससे श्रीराम प्रसन्न होते हैं।' तब अपने प्रभु श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया।

मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते



नहीं चाहता था। उसने मृत्यु को चकमा देने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय सोचा। एक समय ऐसा आया कि जब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मृत्यु का समय अब समीप आने लगा है। मृत्यु का समय निकट जानकर उसने अपने जैसी कई मूर्तियाँ बनाकर अपने हाल कमरे में सजाकर रख दीं और स्वयं भी उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसे अब मृत्यु का देवता पहचान नहीं सकेगा और वह बच जाएगा।

कहते हैं जब यमराज उसे लेने के लिए आए तो इतनी सारी सजीव मूर्तियों के बीच छिपे मूर्तिकार को खोज नहीं पाए। तब उन्होंने उसे ढूँढ़ने के लिए युगत भिड़ाई और कहा,जिस भी मूर्तिकार ने ये सुन्दर और सजीव मूर्तियाँ बनाई हैं, उसने वाकई

न्यूज़ अपडेट

महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ धारण करेंगे कान्हा की भूमि से भेजे वस्त्र एवं श्रृंगार

मथुरा (उप्र): महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ एवं माता पार्वती कान्हा की भूमि से भेजे गए वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री प्रतीकात्मक रूप से धारण करेंगे तथा फलों एवं मिठाई का भोग लगाएंगे। यह जानकारी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने सोमवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि रविवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान से भगवान शिव एवं मां गौरी के वस्त्र, मां का श्रृंगार, आभूषण, इत्र इत्यादि तथा लड्डू, मेवे एवं फल भोग लगाने के लिए भेजे गए।

उन्होंने बताया कि यह सब सामग्री रविवार को ढोल, मृदंगा, मंजीरे, बैँड-बाजा आदि की मंगल ध्वनि के बीच शोभायात्रा के रूप में अन्नपूर्णाेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर भगवान श्रीकेशवदेवजी, मां योगमायाजी, श्रीगर्भ-गृहजी होते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार से बाबा विश्वनाथ के धाम वाराणसी के लिए खाना की गई थी, जो वहां पर सकुशल पहुंच चुकी है।

उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई से अपराध दर में आई गिरावट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्य की 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी, जिसमें कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की

उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, फलस्वरूप अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट हुई तथा आम जनता के साथ-साथ निवेशकों का भी विश्वास बढ़ा है। खन्ना ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आधुनिक तकनीक पर आधारित पुलिस प्रणाली को बढ़ावा देकर सुधारों को नई दिशा दी गई है, सीसीटीवी, 'डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम' और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पुलिस की कार्यक्षमता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे जनता में निर्भीक होकर शिकायत दर्ज कराने का वातावरण तैयार हुआ और अपराध नियंत्रण को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है तथा 'सेफ सिटी परियोजना' के तहत 'महिला पुलिस बीट', सीसीटीवी नेटवर्क और 'एंटी-रोमियो स्कॉड' की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

भाजपा राष्ट्र को पहले, जबकि विपक्ष स्वार्थ की पहेले रखता है: नितिन नवीन

पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और स्वयं को सबसे अंत में रखती है, जबकि विपक्ष के लिए स्वार्थ ही पहला और आखिरी होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने गृहनगर पटना की पहली यात्रा पर पहुंचे नवीन ने पार्टी की बिहार इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस दौर में जंगल रास को उखाड़ फेंकने में भूमिका निभाई, जब पर्व बांटना भी जोखिम से भर होता था। उन्होंने कहा, त्याग की वही भावना आज भी जारी है। मुझे केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जाने का अवसर मिला, जहां पार्टी कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के संसर्ग कर रहे हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को पहले, पार्टी को दूसरे और स्वयं को सबसे अंत में रखती है। हमारे विरोधियों के लिए स्वार्थ ही पहला और आखिरी होता है। वैंतालीस वर्ष की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नवीन ने कार्यकर्ताओं को आश्चस्त करते हुए कहा, हमारे पास मजबूत वांच टावर है। बुध स्तर का कार्यकर्ता निश्चित रह सकता है कि उसके काम का संज्ञान लिया जा रहा है और वह प्रदेश इकाई का अध्यक्ष, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। मैं आपके सामने इसका उदाहरण हूं।

सभी देवताओं के पास अपनी-अपनी शक्तियां हैं जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती लेकिन हनुमान खुद ही शक्ति से संचालित देव हैं। वे सर्वशक्तिशाली हैं लेकिन अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। अपूर्व बलशाली होते हुए भी वे भक्ति की अनुपम मिसाल हैं। उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर श्रीराम ने ही उन्हें वरदान दिया था कि मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे मंदिर होंगे और लोग अपने सकंटों के निवारण के लिए तुम्हारी उपासना करेंगे। हनुमान भक्तों की पुकार पर तुरंत ही उनके कष्ट हरते हैं। कलियुग में हनुमान सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं। वे भक्तों का हर तरह से मंगल करते हैं।

वेद पुराणों में हनुमानजी को अजर-अमर कहा गया है। शास्त्रों में सप्त चिरंजीवों में हनुमान, राजा बाली, महामुनि व्यास, अंगद, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विभीषण सम्मिलित हैं। चूँकि हनुमान सदैव स्र धरा पर मौजूद हैं तो उनकी उपासना किसी भी तरह से की जाए निश्चित फलदायी होती है। (उर्वशी)

तार छूट नहीं सकता। सार रूप में हम यही समझ सकते हैं कि जन्म से लेकर अन्तिम दिन तक भौत की तलवार हमारे सिर पर लटकती रहती है। जैसे कबूतर अँधे बन्द कर ले और सोचे कि बिड़ली चली गई है और अब तो मैं सुरक्षित हो गया हूं! वास्तव में इस प्रकार सोचना उसकी भूल होती है। वह बिड़ली तो अपना शिकार सरलता से पकड़ लेती है और वह बेचारा कबूतर सोचता ही रह जाता है।

इसी प्रकार यदि हम अपने सिर पर लटकती तलवार को देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं तो मृत्यु को कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला। पूर्वजन्म कृत कर्मों के अनुसार मिला हुआ हमारा समय जब पूरा हो जाएगा तब वह मृत्यु हमारे शरीर में विद्यमान इस जीव या आत्मा को बिना आगे-पीछे देखे लेकर चल पड़ेगी। जीव को विवशता से मृत्यु का दामन थामना ही पड़ता है। जो महात्मा जन होते हैं, वे हसते-हसते मृत्यु को गले लगा लेते हैं। इसके विपरीत अर्धर्म करने वाले लोग रोते-रोते मृत्यु के साथ जाते हैं।

मृत्यु तो एक-न-एक दिन हमारे पास आनी ही है इसलिए उससे क्या डरना? महााजग भर्तृहरि जी का कहना है-**अथैव मरणं युगान्ते वा धीराः न्यायात्यन्तः पदं न प्रविचलन्ति।** अर्थात् धीर लोग अपने न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित होते क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। उसका स्वागत प्रसन्न होकर करना चाहिए। इसका डर उन लोगों को होता है जो अपने सच्चाई व ईमानदारी के ठीक रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे हंसते हुए उसे गले लगाने के लिए उसकी प्रतीक्षा में तैयार बैठे रहते हैं।

भीड़भाड़ कम करने और सुरक्षा में सुधार के लिए कई अवसररचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई : रेल मंत्रालय

नयी दिल्ली : रेल अवसररचना परियोजनाओं के एक व्यापक समूह को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में भीड़भाड़ को खत्म करना, लाइन क्षमता बढ़ाना, सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना और यात्रियों तथा माल की आव-जाही को तेज व अधिक विश्वसनीय बनाना है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय की ओर से मीडिया में जारी एक बयान में कहा गया है कि इन स्वीकृतियों में दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिण-पूर्व रेलवे शामिल हैं, जिनमें लाइन दोहरीकरण, तीसरी और चौथी लाइन, बाईपास कॉरिडोर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली शामिल हैं। बयान में कहा गया, "श्राखंड में बारबेंडा-दमरुघुत दोहरीकरण और दमरुघुत-बोकारो स्टील सिटी की तीसरी और चौथी लाइनें दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत प्रमुख क्षमता विस्तार परियोजनाएं हैं तथा भारत के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर की आधारशिला हैं।"

बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस मंगलवार को देने की तैयारी में विपक्ष

नयी दिल्ली : लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को "बोलने की इजाजत नहीं देंगे" तथा कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को सौंप सकता है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम तक प्रस्ताव संबंधी नोटिस पर 102 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, हालांकि विपक्ष के एक प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई सांसदों के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को सौंपा जा सकता है।

दिल्ली सरकार ई-रिक्षा को विनियमित करने के लिये नीति तैयार कर रही है

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार शहर में ई-रिक्षा को विनियमित करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है, ताकि इन वाहनों के कारण होने वाली यातायात की भीड़भाड़ से निपटा जा सके और साथ ही परिवहन के इस साधन को अंतिम छोर तक पहुंचने के एक प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सके। अधिकारियों ने सोमवार को कहा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ई-रिक्षा को विनियमित करने के लिए एक नीति की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इन न केवल अंतिम छोर तक पहुंचने का एक माध्यम है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है।

दिल्ली: सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए व्यक्ति को 68.56 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

नयी दिल्ली : दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बवाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने के कारण अपना दाहिना पैर गंवा देने वाले एक व्यक्ति को 68.56 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सुनील कुमार पंडित पवन कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पवन की मोटरसाइकिल को आठ जून 2021 को पृष्ठ खुद में वाल्मीकि अस्पताल के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसका दाहिना पैर फट गया था। न्यायाधिकरण ने चार फरवरी को पारित आदेश में कहा कि यह साबित हो गया है कि दुर्घटना ट्रक चालक के लापरवाही से और तेज रफ्तार से वाहन चलाने की वजह से हुई, जिसमें पवन को गंभीर चोटें आईं।

माओवाद से समाज को कभी लाभ नहीं हुआ, इससे विनाश ही हुआ है : शाह



सरकार की माओवादी पुनर्वास नीति सबसे आकर्षक है।" उन्होंने इसको लेकर भी चिंता जतायी कि जो नक्सली अभी भी डटे हुए हैं, उनमें युवा आदिवासी लड़कियां भी शामिल हैं। शाह ने कहा, "उन्हें (युवा आदिवासी लड़कियों को) पुनर्वास के लिए भेजा जाना चाहिए क्योंकि उनके

सामने पूरी जिंदगी पड़ी है।" शाह ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए जाने का आश्वासन देते हुए चेतावनी दी कि जो लोग गोली चलाना जारी रखेंगे, आईईडी लगाएंगे और विद्यालयों एवं अस्पतालों को आग लगाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा, "सशस्त्र हिंसा का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर कोई हथियार उठाएगा, तो जवाब भी हथियारों से ही दिया जाएगा। माओवाद ने किसी भी समाज को लाभ नहीं पहुंचाया और जहां भी यह मौजूद रहा, वहां विनाश फैलाया, जिसमें कोलंबिया, पेरू और कंबोडिया जैसी देश भी शामिल हैं।" शाह ने शेष सशस्त्र नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए कहा, "हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई अपने आदिवासी भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए है। जब आईईडी लगाए जाते हैं, तो निर्दोष बच्चों की जान जा सकती है या वे स्थायी रूप से अपंग हो सकते हैं। यह क्रूरता कहां से आती है?"

बजट में लिखी बातों को न तो पढ़ते और न ही सुनते हैं राहुल गांधी : स्मृति ईरानी



है, जो हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय में जुटे लोगों के लिए है। ऐसे आरोप लगाने वाला व्यक्ति (राहुल गांधी) न तो ठीक से सुनता है और न ही पढ़ता है। अगर उन्होंने बजट को पढ़ा होता, तो उन्हें बजट में इस प्रावधान की जानकारी होती।" राहुल गांधी द्वारा बजट को उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद बनाने पर ईरानी ने कहा, "बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का उल्लेख

वैश्विक अस्थिरता की स्थिति में भारत का पेट्रोलियम भंडार 74 दिनों के लिए पर्याप्त : पुरी

नयी दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि वैश्विक उथल-पुथल की किसी स्थिति में उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 74 दिनों के लिए पर्याप्त है। पुरी उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए, जो तेज गति से विकास कर रहा है, व्यवहार्य और सुरक्षित तेल भंडार आवश्यक है, ताकि वैश्विक उथल-पुथल की स्थिति में वह कमजोर स्थिति में नहीं हो। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी तट के साथ-साथ पूर्वी तट पर भी तेलशोधक संयंत्र हैं। पुरी ने कहा,"

भारत ने नेपाली सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे



नयी दिल्ली : भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि उसने भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली सेना को 50 सैन्य उपयोग वाहन सौंपे हैं, जो दोनों सेनाओं के बीच अटूट बंधन को रेखांकित करता है। भारतीय सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। उसने लिखा, रक्षा सहयोग। भारतीय सेना ने भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली सेना को 50

यह दावा निराधार है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था : सूत्र

नयी दिल्ली : लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं का यह दावा निराधार है कि बीते बृहस्पतिवार को सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोई "तात्कालिक खतरा" नहीं था, जबकि उस दिन सदन के घटनाक्रमों से लग रहा था कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने यह स्पष्टीकरण उस वक्त जारी किया है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री पर सदन में किसी निपक्षी सदस्य द्वारा "हमला करने" का कोई सवाल ही नहीं उठता तथा यदि किसी ने कोई ऐसी हरकत करने को कहा भी हो तो प्राथमिकी दर्ज करके उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

ईंडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के खिलाफ विभिन्न मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह और उससे जुड़ी इकाइयों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा'को एसआईटी का नेतृत्व संघीय जांच एजेंसी की मुख्यालय जांच इकाई (एचआईयू) के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और इसमें लगभग आधा दर्जन अन्य जांच अधिकारी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के खिलाफ मामलों की समीक्षा करते हुए ईडी को "निष्पक्ष, स्वतंत्र, त्वरित

और तटस्थ" जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने समूह से जुड़े मामलों की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से साठगांठ, मिलीभगत, साठगांठ और साजिश (यदि कोई हो) की जांच करने और अपनी जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कहा था। ईडी पिछले साल से अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रही है और अब तक उसने हम शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की हैं और करीब 12 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईसीआईआर पुलिस प्राथमिकी के समकक्ष ईडी की कार्रवाई है।

इसरो ने चंद्रयान-4 लैंडर के लिए लैंडिंग स्थल की पहचान की

बेंगलुरु : इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन शुरू होने से कम से कम दो साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अपने लैंडर के उतरने के लिए एक स्थल की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लाए जाएंगे। यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने पहले कहा था, हम चंद्रयान-4 के लिए 2028 का लक्ष्य रख रहे हैं। इसरो के अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने मॉस माउटन

(एमएम) क्षेत्र के चार स्थलों का चयन किया और उनमें से एक को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए उपयुक्त पाया। मॉस माउटन चंद्रमा का एक क्षेत्र है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने एमएम-1, एमएम-3, एमएम-4 और एमएम-5 स्थानों की पहचान की, जिनमें से एमएम-4 को लैंडिंग के लिए चुना गया। उन्होंने कहा, मॉस माउटन क्षेत्र के चारों स्थलों को उनकी ऊंचाई और ज़मीन की आकृति के आधार पर ऑर्बिटर हाई रिजॉल्यूशन कैमरा (ओएचआ-रसी) और विभिन्न तस्वीरों की मदद से पूरी तरह से जांचा गया।

डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए विमानन कंपनियों को 352 कारण बताओ नोटिस जारी किए

नयी दिल्ली : सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले दो साल में विभिन्न उल्लंघनों के लिए एयरलाइन कंपनियों को 352 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 के दौरान इंडिगो और एअर इंडिया को क्रमशः 98 और 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नारार विमानन राज्य मंत्री सुरीतीधर मोहोले ने एक सदन के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के

दौरान नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया एक्सप्रेस को 65, स्पाइसजेट को 45, आकासा एयर को 17, सरकारी स्वामित्व वाली एरलायंस एयर को 23, फ्लाय बिग को 12, एआईएक्स कनेक्ट को 7 और स्टार एयर को 1 कारण बताओ नोटिस जारी किए। मोहोले ने बताया कि कुल 352 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनमें से 139 नोटिस के संबंध में संबंधित विमानन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। 113 मामलों में महानिदेशालय द्वारा चेतावनी जारी की गई, जबकि 7 मामलों में संतोषजनक जवाब प्राप्त हुए।

भारत ने सेशेल्स के लिए 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की



नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ व्यापक बातचीत की जिसके बाद भारत ने सोमवार को इस द्वीप राष्ट्र को विकास सहायता के रूप में 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। दोनों पक्षों ने सतत विकास, व्यापार, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिपत्र पर भी सहमति व्यक्त की। हर्मिनी भारत की छह दिवसीय यात्रा पर आए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मोदी ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा, "भारत और सेशेल्स केवल भौगोलिक रूप

से ही नहीं बल्कि इतिहास, विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत आधारशिला रही है। उन्होंने कहा, "हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, आज हम 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एक विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने जा रहे हैं।" मोदी ने कहा कि यह पैकेज "ठोस परियोजनाओं को समर्थन देगा, जो सामाजिक आवास, परिवहन सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू की जाएंगी।

भारत ने सेशेल्स के लिए 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की

संसद में चर्चा नहीं होने का नुकसान विपक्ष को होगा: रीजीजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि अगर संसद में चर्चा नहीं होती है तो इसमें विपक्ष का नुकसान है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है और उसे सदन में कोई भी प्रस्ताव पारित कराने में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार चाहती है कि हर चीज चर्चा के बाद ही पारित हो। संसद पवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए रीजीजू ने यह भी कहा कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन विपक्ष के पास उन्हें हटाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष के पद का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि कुछ सांसद अध्यक्ष की मेज और अधिकारियों की मेज पर चढ़ गए और अध्यक्ष के कक्ष में घुस गए। मंत्री ने कहा कि सरकार अध्यक्ष से और कड़ी कार्रवाई करने को कह सकती थी, जबकि उसने सिर्फ आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के फैसले से सहमत जताई। उनके मुताबिक, सरकार सदन चलाना चाहती है और विपक्ष से बात करने के लिए तैयार है। रीजीजू ने कहा, अब मैंने सुना है कि राहुल (गांधी) चार बिंदुओं (शर्तों) के साथ अध्यक्ष से मिलने गए थे, जिनमें सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग भी शामिल थी। उन्होंने ये बातें मुझसे नहीं कही हैं। सरकार की ओर से हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम शुरुआत से ही और आज भी चाहते हैं कि सदन ठीक से चले। लेकिन मैं उस स्थिति से सहमत नहीं हो सकता जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलें, आरोप लगाएं, फिर हंगामा करें और दूसरों को बोलने न दें। ऐसा नहीं होगा।"

सभापति ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो वह अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष के

नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने देना बहुत अजीब है : थरूर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए और सदन में एक पक्ष को बोलने के अधिकार से वंचित किया जाना बहुत अजीबो-गरीब है। थरूर सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करने वाले थे लेकिन आसम की ओर से राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने सवालिया अंदाज में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और सरकार आखिर क्या चाहते हैं? उन्होंने लोकसभा की बैठक के दिनां भर के लिए स्थगित होने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, स्थिति बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि अध्यक्ष या सरकार सदन में बजट पर चर्चा चाहते हैं या नहीं। सदन की 70 वर्षों से अधिक की एक पुरानी परंपरा है कि पहले नेता प्रतिपक्ष और फिर संसदीय कार्य मंत्री को बोलने का अवसर दिया जाता है।

नेता से कहा था कि पहले वह विषय बताएं जो वह सदन में उठाना चाहते हैं। दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने केंद्रीय बजट

पर चर्चा की शुरुआत के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा। थरूर ने उसने पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगी। पीठासीन

आयकर की दरों में बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग निराश : राघव चड्ढा

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग निराश है। उच्च सदन में 2026-27 के बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आप सदस्य ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि आयकर की सीमा में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने से लोगों में खासकर वेतनभोगी वर्ग में निराशा है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी आय कर से मिली राशि कापीोट कर से अधिक हो गयी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आयकर मानक कटौती की सीमा



75,000 रुपये से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपये की जाए। उन्होंने कहा कि अगर आयकर की सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं तो बचत पर राहत दी जानी चाहिए और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुद्रास्फीति से संबद्ध वेतन व्यवस्था लागू किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को गौर करना चाहिए कि विदेशी

भारत और यूनान ने रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए



नयी दिल्ली : भारत और यूनान ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो साझेदारी को बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय रोलैपमें विकसित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूनान ने द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना के बाद यह समझौता हुआ। बाद में

'एक्स' पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने यूनान की उस घोषणा का भी स्वागत किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी गुरुग्राम स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में तैनात किया जाएगा। सिंह ने कहा, आज नयी दिल्ली में हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रिय रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूनान ने द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया।

लोकसभा: राहुल को बजट के अलावा अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिली, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित



नयी दिल्ली : लोकसभा में बजट पर चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अन्य विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बीच कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष

राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले अपनी बात रखने की अनुमति देने का वादा किया है, वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि कांग्रेस नेता की बात शून्य-प्रतिपक्ष सही नहीं है और अध्यक्ष ने कांग्रेस

रहे हैं।" पीठासीन सभापति संध्या राय ने कहा कि उनके पास किसी तरह का नोटिट नहीं है और वर्तमान स्थिति में वह केवल बजट पर बोलने की अनुमति दे सकती हैं।

